भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4562

27 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन

†4562. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) की वर्तमान स्थिति तथा देशभर में इसका राज्यवार, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में कार्यान्वयन संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान एनयूडीएम के अंतर्गत आवंटित तथा उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) शहरी सेवा प्रदायगी में वृद्धि करने के लिए एनयूडीएम के अंतर्गत विकसित प्रमुख डिजिटल गवर्नेंस पहल तथा अवसंरचना कौन सी हैं;

(घ) क्या सरकार ने दक्षता, पारदर्शिता तथा नागरिक सेवाओं के संदर्भ में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) पर एनयूडीएम के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा एनयूडीएम को स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) तथा अमृत जैसे अन्य शहरी मिशनों के साथ एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं तथा इस पहल हेतु भविष्य में विस्तार की योजनाएं, यदि कोई हों, तो क्या हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ) 2025-29 की अवधि के लिए राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) की योजना विचाराधीन है। वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान 1150.02 करोड़ रु. है। हालांकि, वित्त मंत्रालय के निधि प्रवाह दिशानिर्देशों के अनुसरण में, संशोधित अनुमान चरण में निधि को 1150.02 करोड़ रु. से घटाकर 108.70 करोड़ रु. करने का अनुरोध किया गया था। शहरी सेवा प्रदायगी की अवधारणा के प्रमाण के रूप में अर्बन प्लेटफॉर्म फॉर डिलिवरी ऑफ ऑनलाइन गवर्नेंस (यूपीवाईओजी) पोर्टल का विकास किया जा रहा है और इसका पूर्ण शुभारंभ कार्यान्वयन के बाद मिशन अवधि के दौरान होगा।

*****